कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक से मांगा तीन दिन में जवाब

आरजीपीवी में प्रश्नपत्र चोरी से मचा हड़कंप

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के परीक्षा विभाग (एग्जाम सेल) से पीजी परीक्षाओं के नौ विषयों के प्रश्नपत्र चोरी होने का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति प्रो. आलोक शर्मा ने परीक्षा नियंत्रक एवं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डायरेक्टर डॉ. अर्चना तिवारी से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

- पीजी परीक्षा के 9 विषयों के प्रश्नपत्र परीक्षा शाखा से गायब।
- न ताला टूटा, न कमरे में तोड़फोड़, अंदरूनी संलिप्तता की आशंका।
- कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्चना तिवारी से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा।
- गांधीनगर थाने में एफआईआर, पुलिस और एफएसएल जांच में जुटी।
- घटना के बाद पीजी परीक्षा स्थगित करनी पड़ी।
- कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सरकार पर साधा निशाना, युवाओं के भविष्य पर चिंता जताई।
- परीक्षा शाखा में सीसीटीवी कैमरे नहीं, जांच में आ रही दिक्कत।
- मामले के बाद परीक्षा सुरक्षा और गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः तीन जुलाई को आयोजित होने वाली पीजी परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा शाखा से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि न तो किसी ताले को तोड़ा गया और न ही कमरे में तोड़फोड़ के निशान मिले। इस कारण शुरुआती जांच में विश्वविद्यालय के किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है।

कुलपति द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रश्नपत्रों का

अनाधिकृत रूप से लुप्त होना अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है। निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से पूरे घटनाक्रम का विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।

इधर, गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस के अनुसार परीक्षा शाखा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से जांच में कठिनाई आ रही है। अब तक घटना से जुड़ा कोई वीडियो साक्ष्य भी नहीं मिला है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागीय जांच शुरू की

मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में अब आरजीपीवी की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं के प्रश्नपत्र चोरी नहीं बल्कि लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब परीक्षा की गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं है तो युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। बार-बार इस तरह की घटनाएं होना व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रश्नपत्र चोरी की घटना के बाद शुक्रवार को आयोजित पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागीय जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस और एफएसएल की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना ने प्रदेश में प्रतियोगी और विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में इस हाई-प्रोफाइल मामले का खुलासा कब तक होता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

महिलाओं की सहकारी सोसायटियां बनाने में अग्रणी बनेगा प्रदेश : सारंग

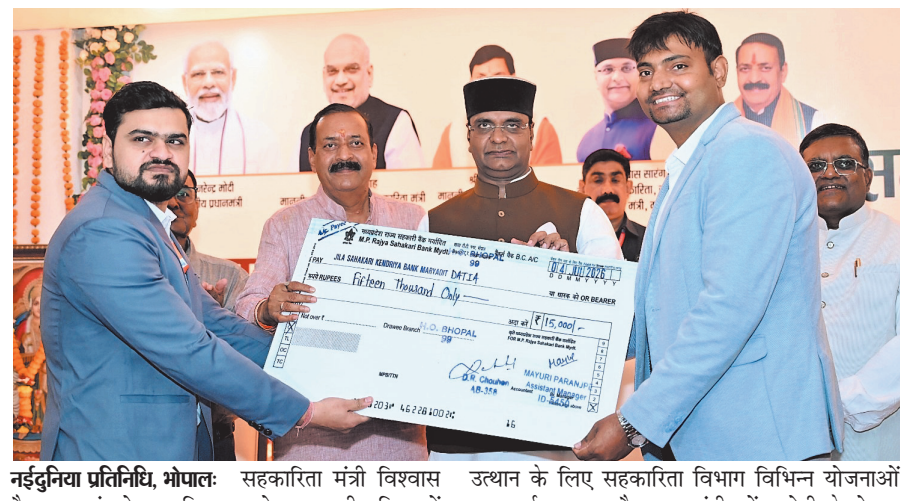

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश जल्द ही महिलाओं की सहकारी सोसायटियां स्थापित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इसकी शुरुआत अगले माह से की जाएगी। वे रविवार को अपेक्स बैंक में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश सहकारिता क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऑनलाइन ऑडिट, कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्द ही बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। युवा, महिला और किसान वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता विभाग विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है तथा कॉपरेरिट और को-ऑपरेटिव मॉडल के समन्वय से विकास को गति दी जा रही है। समारोह में अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सहकारिता सप्ताह के दौरान जिलों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम हुए तथा पौधरोपण भी किया गया। प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अमानत संग्रहण लक्ष्य की पूर्ति में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विदिशा को प्रथम, जबकि दतिया बैंक को द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। पैक्स सदस्यता अभियान और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण का स्वास्थ्य संगठनों ने किया विरोध, बोले-

फैसला वापस ले सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के संचालन को निजी संस्थाओं के हवाले करने के फैसले का स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और जनस्वास्थ्य से जुड़े संगठनों ने विरोध किया है। रविवार को भोपाल में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में संगठनों ने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय निजीकरण की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) को मंजूरी दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। पहले चरण में रीवा, देवास और गुना जिलों के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट में

शामिल किया गया है।

पत्रकार वार्ता में एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आनंद शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले ही मातृ मृत्यु दर जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निजीकरण स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजीकरण के बजाय डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पद भरने तथा सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। डॉ. शर्मा ने आशंका जताई कि सरकारी संस्थानों के निजीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

वहीं, मध्यप्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल उपचार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी), पोस्टमार्टम और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। इनकी रिपोर्ट अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होती है। ऐसे में यदि इन सेवाओं का संचालन निजी संस्थाओं के हाथों में जाता है तो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं।

संगठनों ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार चाहती है तो उसे स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करनी चाहिए, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करनी चाहिए और सरकारी अस्पतालों को आधुनिक संसाधनों एवं पर्याप्त स्टाफ से सशक्त बनाना चाहिए। उनका कहना है कि निजीकरण से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 55 जिला अस्पताल, 51 सिविल अस्पताल, 158 उप जिला/सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्र तथा पांच पॉलीक्लिनिक संचालित हैं।

सतगढ़ी में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, 15 हजार रोजगार के अवसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 जुलाई को राजधानी के सतगढ़ी क्षेत्र में विकसित किए जा रहे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन एवं शिलान्यास करेंगे।

डॉ. मुखर्जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश और देश के लगभग 200 उद्योगपति, निवेशक तथा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

करीब 173 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। परियोजना में आधुनिक सड़क एवं परिवहन नेटवर्क, आईटी और एआई आधारित सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स तथा स्मार्ट औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। पार्क को 'वर्क-लिव-ग्रो' मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ कौशल विकास, नवाचार और

आधुनिक जीवन सुविधाओं का भी समावेश होगा।

इस पार्क में उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी, एआई, लॉजिस्टिक्स तथा उभरती तकनीकों से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। परियोजना से लगभग 15 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है, जिससे भोपाल और आसपास के युवाओं को लाभ मिलेगा।

परियोजना की विशेषता 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला विश्वस्तरीय कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर होगा, जिसकी क्षमता 10 हजार से अधिक लोगों की होगी। यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन, व्यापारिक प्रदर्शनियां तथा बड़े औद्योगिक आयोजन आयोजित किए जा सकेंगे।

राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कोलार रोड और प्रस्तावित वेस्टर्न बायपास से बेहतर संपर्क इस क्षेत्र को निवेश के लिए आकर्षक बनाएगा। पार्क में एससीएडीए आधारित जल प्रबंधन, जल एवं सीवेज शोधन संयंत्र, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जैसी पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के प्रेरणास्रोत : डॉ. यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ह्यडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवादी चिंतन आज भी देश को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉ. मुखर्जी के संकल्प को साकार किया गया

और देश की एकता एवं अखंडता को नई मजबूती मिली।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि डॉ. मुखर्जी दूरदर्शी नेता थे। उनकी दूरदृष्टि के कारण पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में डॉ. मुखर्जी ने ऐसी औद्योगिक नीति की नींव रखी, जिसके आधार पर आज देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे, लघु और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने तथा भारतीय भाषाओं और रोजगारपरक शिक्षा के पक्ष में डॉ. मुखर्जी का योगदान उल्लेखनीय रहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है।

देश आज 90 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है और मध्यप्रदेश भी औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को इस वर्ष छह माह में 86 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भोपाल में भारत मंडपम की तर्ज पर विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद आधारित राजनीति की मजबूत नींव रखी। उनके विचारों और आदर्शों के कारण भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए बूथ केवल मतदान केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की इकाई है। कार्यकर्ताओं को डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए।

सत्ता के गलियारे...

• डॉ. शिशिर उपाध्याय

• कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना...

पिछले दिनों सियासत के एक बड़े धुरंधर ने ऐसा तीर छोड़ा कि धनुष किस ओर था, यह कोई नहीं समझ पाया, लेकिन तीर किसे लगा, यह हर कोई जान गया। बयान में किसी का नाम नहीं था, फिर भी कई चेहरे अचानक गंभीर हो गए। कुछ सफाई देने में जुट गए, तो कुछ खामोशी की चादर ओढ़कर बैठ गए। अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि तीर चलाने वाले का निशाना कभी खाली नहीं जाता।

• कब तक बचा पाएंगे हमको...

सत्ता की छतरी फिलहाल धूप और बारिश दोनों से बचा रही है, लेकिन न्याय के मंदिर की घंटियां कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगी हैं। समर्थकों के चेहरे पर भी अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं है। वे धीरे-धीरे पूछने लगे हैं कि आखिर यह सुरक्षा कवच कब तक साथ निभाएगा। राजनीति में मौसम बदलते देर नहीं लगती।

• डोडी पिटवाकर जाति की पुष्टि...

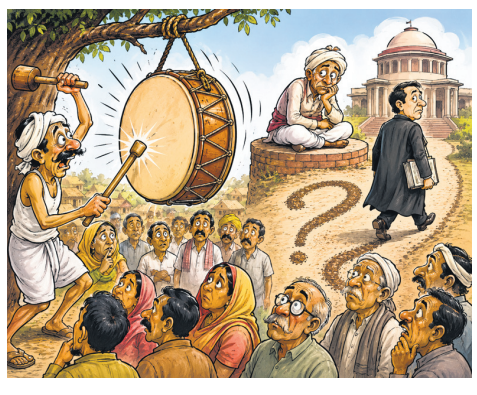

एक समय गांव में डोडी पिटवाने का मतलब सिर्फ सूचना देना होता था, लेकिन अब डोडी किसी का भविष्य तय करने लगी है। गांव में फैसला हो रहा है, जबकि अंतिम फैसला शायद अदालत में होगा। जानकारों का कहना है कि डोडी की आवाज भले गांव तक सुनाई दे, लेकिन उसकी गूंज न्यायालय तक जरूर पहुंचेगी। तब तक कई मौसम बदल जाएंगे और शायद कई कार्यकाल भी पूरे हो जाएंगे।

• सादगी और वजनदारी का संदेश एक साथ...

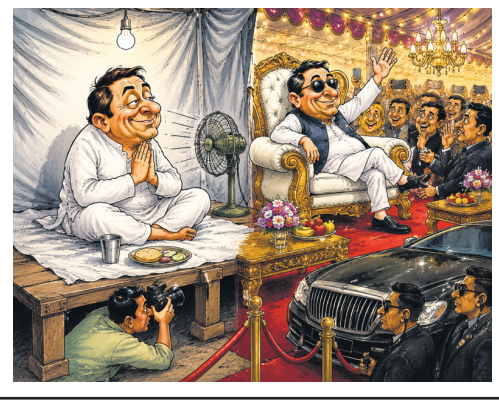

पूर्व क्षत्रप का आयोजन निजी था, लेकिन उसमें मौजूद भीड़ और चेहरों ने उसे सार्वजनिक बना दिया। मंच पर सादगी दिखाई दी और कुर्सियों पर वजनदारी।

अब लोग यही हिसाब लगा रहे हैं कि आखिर संदेश सादगी का था या शक्ति प्रदर्शन का। राजनीति में कई बार खामोशी भी सबसे बड़ा भाषण बन जाती है।

• आखिर हम कहां जाएं, हमारी कौन सुनेगा...

तबादलों की सूची आई तो कई स्थानीय माननीयों की भौंहें भी चढ़ गईं। उनका कहना है कि जिले में वे जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन फैसले कहीं और हो रहे हैं। कुछ ने अपनी पीड़ा ऊपर तक पहुंचा दी है। चर्चा है कि अफसर अब आदेश से ज्यादा इशारों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में समन्वय की जगह असंतोष बढ़े, तो किसी को हैरानी नहीं होगी।

• साहब कुछ भी कहें...

विपक्ष मुद्दे तलाश रहा था, लेकिन अपने ही साहबों ने ऐसा माहौल बना दिया कि विरोध की धार अपने आप कुंद पड़ गई। पहले एक बयान ने आंदोलन की हवा निकाल दी, अब दूसरे बयान ने ईमानदारी का ऐसा प्रमाणपत्र बांट दिया कि कार्यकर्ता ही असमंजस में पड़ गए। अब पार्टी के गलियारों में चर्चा है कि विरोधियों से लड़ाई बाद में होगी, पहले अपनों के बयानों पर ही पहरा लगाना पड़ेगा। आखिर राजनीति में कई बार एक बयान, सौ रणनीतियों पर भारी पड़ जाता है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। * फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com